

नविवारक नरिध

स्रोत: हदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने मुरतुजा हुसैन चौधरी बनाम नगालैंड राज्य, 2025 में पुनः पुष्टिकी क नविवारक नरिध एक कठोर उपाय है, जसके लयि संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन आवश्यक है ।

- इस फैसले में उचति औचित्य के अभाव तथा कानूनी सदिधांतों का उल्लंघन करने के कारण नगालैंड के नरिध आदेशों को रद्द कर दिया गया ।

नविवारक नरिध के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय क्या है?

- मामला: दो व्यक्तियों को मादक पदार्थ जब्ती के बाद स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार नविवारण अधनियम, 1988 (PITNDPS अधनियम) के तहत नविवारक रूप से हरिसत में लयिा गया था, जो पुलसि के इस आरोप पर आधारति था क रिहिा कयि जाने पर वे फरि से तसकरी शुरु कर देंगे, लेकिन इसके लयि कोई अलग आधार नहीं था ।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया क हरिसत आदेशों में पृथक, वशिष्ट आधारों का अभाव होने के कारण PITNDPS अधनियम की धारा 6 का उल्लंघन हुआ है ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने टपिणी की क हरिसत में लयि गए ऐसे लोग जो अंगरेजी नहीं समझते थे, उन्हें मौखिक रूप से उनकी भाषा में जानकारी दी गई, लेकिन इसे अपर्याप्त माना गया । सर्वोच्च न्यायालय ने हरकिसिन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1962) मामले का हवाला दिया, जसमें कहा गया था क हरिसत के आधार के बारे में केवल मौखिक संचार अपर्याप्त है ।
- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया क नविवारक नरिध से मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है और इसमें वैधानिक मानदंडों का सख्ती से पालन करना चाहयि । परिणामस्वरूप, न्यायालय ने नरिध आदेशों को रद्द कर दिया ।

नविवारक नरिध क्या है?

- परिचय: इसका तात्पर्य संभावति गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के क्रम में कसिी व्यक्तिको बनिा सुनवाई के हरिसत में लेना है ।
 - दंडात्मक नरिध के वपिरीत (जसमें उचति प्रक्रयिा और दोषसदिधा नयिमों का पालन कयिा जाता है) नविवारक नरिध के तहत संदेह के आधार पर व्यक्तगित स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता है ।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गरिफ्तारी तथा नरिध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है । इसका पहला भाग आपराधिक जाँच से जुड़े सामान्य वधिकि मामले से संबंधति है जबकि दूसरा भाग नविवारक नरिध से संबंधति है ।
 - कसिी व्यक्तिको बनिा वधिवारण के तीन माह तक हरिसत में रखा जा सकता है, जब तक क सलाहकार बोर्ड (जसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लयि अरुहति व्यक्तशामलि होते हैं) द्वारा अवधि न बढ़ा दी जाए ।
 - हरिसत में लयि गए व्यक्तिको हरिसत में लयि जाने के कारणों के बारे में सूचति कयिा जाना चाहिए, जब तक क इससे सार्वजनिक हति को नुकसान न पहुंचे । उन्हें वधिकि प्रतनिधित्व का अधिकार है, हालाँकि कुछ मामलों में इस अधिकार को प्रतबिधति कयिा जा सकता है ।
- नविवारक नरिध से संबंधति प्रमुख कानून:
 - राष्ट्रीय सुरक्षा अधनियम, 1980: राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था को खतरे से बचाने के लयि नज़रबंदी की अनुमतिका प्रावधान ।
 - वधिविरुद्ध क्रयिा-कलाप (नविवारण) अधनियम, 1967: भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरा पहुँचाने वाली गतिविधियों की रोकथाम कयिे जाने का प्रावधान ।
 - लोक सुरक्षा अधनियम, 1978: इसका उपयोग जम्मू-कश्मीर में लोक व्यवस्था और सुरक्षा के आधार पर नविवारक नरिध के लयि कयिा जाता है ।
 - न्यायिक नरिणय: अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य (2023) में, सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया क नविवारक नरिध एक असाधारण उपाय है और इसका मनमाना रूप से इस्तेमाल नहीं कयिा जा सकता ।
 - जसीला शाजी बनाम भारत संघ मामले (2024) में, सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया क बिंदियों को उनकी हरिसत में आक्षेप करने हेतु उचति अवसर सुनश्चिति कयिा जाना चाहयि ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/preventive-detention-7>

